Resolutions. The Minister will intervene and the Mover also will reply.

Now, let us take up the Half-an-Hour Discussion.

17-30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

TERMINAL BENEFITS TO BEAS-SUTLAJ LINK WORKERS, TALWARA.

MR. CHAIRMAN: Now let us take up the half-an-hour discussion. Shri Bhagat Ram.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): Now you are calling him. You are really creating...

MR. CHAIRMAN: I will show you the records and you will be satisfied.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I could have raised the matter of quorum and got the House adjourned but I do not want to do it.

श्री भगत राम (फिल्लौर) : सभापति महोदय, मैंने 9 अगस्त, 1978 को एक क्वैशचन भेजा था जिसका नम्बर था 3456/355। क्वैश्चन यह था :

(a) Whether the Co-ordination Committee of Beas-Sutlej Link workers of Talwara had drawn Government's attention towards discrimination while giving terminal benefit to the workers;

(b) How many workers got terminal benefit and the number of those who did not get the same;

(c) whether there is a great resentment among the workers against this discrimination and the Co-ordination Committee has started agitation; and

(d) whether Government propose to give terminal benefit to the remaining workers?

इसका रेप्लाई मुझे यह दिया दिया गया था :

(a) Government is not aware of any discrimination in the grant of benefits under the rules, to the workers?

(b) to(d). Do not arise.

मैं समझता था कि शायद मिनिस्टर साहब को गलत-फहमी हुई हो, उनको इस बात की जानकारी न हो इसलिए मैं ने फिर इस सेशन में इसी क्वैश्चन को रिपीट किया, उसका रेफ़ेन्स देकर मैंने पूछा :

(a) under which rule some workers had been given terminal benefit and others denied;

(b) the number of those who got the terminal benefit and those who were denied; and

(c) whether Government propose to give terminal benefit to the remaining workers?

मुझे अफसोस है कि इस बार भी मुझे जो उत्तर दिया गया उस में पहले की गलती पर परदा डालने की कोशिश की गई । मेरे क्वैश्चन नं० 3538 का गलत उत्तर दिया गया । इस में कहा गया कि 1947 का जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है उस के क्लाज़ 25 (एफ) (के) के अन्डर रिट्रेन्चमेन्ट कम्पेनसेशन दे दिया गया है । अब इसकी जो असली पोज़ीशन है वह मैं बताना चाहता हूं। यह जो कम्पेंसेशन ऐक्ट है उस के अंतर्गत जो बताया गया है वह असली टर्मिनल बेनिफिट नहीं है । थोड़े से वर्कस को तीन तीन महीने का टर्मिनल बेनिफिट के रूप में वेतन मिला है जबकि वहां तलवाड़ा और सुन्दर नगर जो डैम्स हैं उन पर 50 हजार से ज्यादा वर्कर्स काम करते रहे हैं। उन्होंने अपनी जिन्दगी का बहुत ही कीमती भाग वहां पर लगाया है । इस से पहले उन में से बहुत से वर्कर्स ने भाखड़ा डैम पर काम किया था। उन्होंने सर्दी गर्मी की कोई परवाह न करते हुए दिन रात काम किया था। 425 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई । हजारों लोग नाकारा हो गए । एक्सीडेंन्ट में किसी का बाजू टूट गया, किसी की टांग टूट गई और किसी का कुछ और हो गया । इन लोगों नें इतनी मेहनत कर के डैम को तैयार किया जिसका आज देश में बिजली और सिचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है । यह मजदूर जो कथित हरा इनकलाब लाये उस से करोड़ों का बेनिफिट आज देश को मिल रहा है । लेकिन जो ऐसे मजदूर हैं इन लोगों को टर्मिनल बेनिफिट नहीं दिया गया, जब कि दूसरे लोगों को--मैं उन के लिये विरोध नहीं करता हूं, मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है — दिया गया, जो इन्जीनियर्स थे या ऐसे वर्कर्स थे, जो रेगुलर थे । लेकिन जिन्होंनें अपनी जान की बाज़ी लगा दी, आप के डैम को तैयार किया, उन को नहीं मिला । इस लिये मुझे उम्मीद है—मिनिस्टर साहब आज इसी हाउस

[श्री भगत राम]

एनाउन्स करेंगे कि उन के साथ जो डिस्क्रीमिनेशन किया गया है, उस को दूर करने के लिये उन को तीन-तीन महीने का वेतन टर्मिनल बेनिफिट के रूप में, या जो भी नाम आप उस को देना चाहें, दिया जायेगा ।

चेयरमैन साहब, इतना ही नहीं--वहां पर पचास हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिन में से 39 हजार से ज्यादा लोगों को अब तक रिट्रेंच किया गया है । एक सवाल के जवाब में यहां पर बतलाया गया है कि उन में से सिर्फ 9158 को काम दिया गया है, बाकियों को कोई काम नहीं दिया गया है । जिन लोगों को काम दिया गया है, उन की जो लास्ट पे थी, उस को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, भुखमरी की जो वेजेज हैं --उस पर उन को काम दिया गया है । इस लिये जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी देश को खुशहाल बनाने में लगाई हो, उन को काम न मिले, वे भूखे मरें, यह बड़े अफसोस की बात है ।

इस लिये मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा -- जो थीयन डैम का प्रोजेक्ट है, जिस की टेकनीकल-क्लिअरेंस में रुकावट पड़ी हुई है, उस की टेक्नीकल-क्लिअरेंस जल्द से जल्द दी जाये और उस के साथ ही यह कण्डीशन लगा दी जाये कि जो वर्कर्स रिट्रेन्च हुए हैं, उन की लास्ट पे प्रोटेक्ट करते हुए उन को थीयन डैम में लगाया जायगा । इस के साथ ही मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं -- जो वहां पर यूनियन के लीडर्स थे, जिन्होंने वहां वर्कर्स के इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये, उन की ग्रेचुइटी के लिये, उन की डे-टू-डे प्राबल्म के लिये स्ट्रगल लीड की थी, उन को विक्टिमाइज किया गया । उन में से श्री खुशीराम, श्री तलवंत सिंह पप्पू, श्री बलकार सिंह और श्री रघबीर सिंह के खिलाफ कचहरी में झूठे केस चलाये गये और अदालत में वे केस झूठे साबित हुए, अदालत से वे लोग बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन को नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है--यह बड़े अफसोस की बात है । मुझे उम्मीद है-- मिनिस्टर साहब इस के बारे में भी एनाउन्समेंट करेंगे कि उन को बहाल किया जायगा ।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब से यह अपील करना चाहता हूं -- मुझे उम्मीद है वे इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे -- कि जो रिट्रेन्च्ड वर्कर्स हैं, उन को उन की लास्ट पे को प्रोटेक्ट करते हुए बदले में काम दिया जायगा । जब तक उन को काम नहीं मिलता है, तब तक उन के रिट्रेन्चमेन्ट को रोका जायगा और थीयन डैम के क्लिअरेंस के लिये जल्द से जल्द कार्यवाही की जायगी । जो विकटिमाइजेशन किया गया है--वह भी मुझे उम्मीद है जल्द दूर करेंगे और सब मजदूरों को बिना किसी पक्षपात के तीन महीने की तनख्वाह टर्मिनल बेनिफिट के रूप में दी जायगी ।

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): Sir, the hon. Member raised a few points about the Beas-Sutlej Project about the retrenchment benefits. I would like to impress upon him that it is the endeavour of the Government to see that as many people who are retrenched are re-employed elsewhere in various other projects.

In fact, we have suggested to them that as and when new projects are coming up in the neighbourhood, we will try to see that they are accommodated and absorbed in those projects. In fact, Thien Dam is one of them and it is pending techno-economic clearance and as soon as it is cleared, most of them, probably, will be able to be absorbed in that Dam.

Even if that dam is not coming up fast enough, we will try to see that these workers are absorbed in some other projects which are coming up in the neighbourhood. It is in the interest of the workers that we created a cell in that area itself where these people are registered and whenever the vacancies arise these names are sent and they are persuaded to absorb them.

About the terminal benefits the hon'ble Member was telling that some discrimination has been shown. Absolutely no discrimination was shown. It is only under an agreement that retrenchment benefits were given to all those employees who were retrenched as and when the work in a particular area was completed and for the permanent employees some benefits are assured on the basis of some understanding reached between the State governments from where they have been re-

cruited to serve on these projects. It is only because of that some benefits were allowed to be enjoyed by this permanent staff and even these people will get only after they get back to their parent States. That is why I say, there is no discrimination. For instance, the Punjab Government has sanctioned two advance increments to their officers who have worked satisfactorily on the Beas project for at least three years. Like that the Haryana Government has given two advance increments and the Rajasthan Government has also given some project compensatory allowance at the rate of 20 per cent. Whatever terminal benefits were given in view of this assurance given by respective State governments. That is why some of these permanent employees get these benefits. But other workmen—in fact, there were workers working for a number of years—when the question of retrenchment came they placed before the management a number of demands. It is only after discussion with the union representatives that an agreement was reached whereby a number of retrenchment benefits were given to these workers. Sir, if it is a question of helping these employees to get jobs elsewhere we will certainly help and even now I can say that a number of workers have been employed in other projects in the neighbourhood. That is why I am emphasising that there is no discrimination.

With regard to various others problems that he has raised about the hard labour they have put in we do appreciate and sympathise with the workers and we appreciate their sacrificial tendency. That is why we tried to reach an agreement with the Union and tried to settle these disputes by giving them a number of benefits.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उस में एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब सतलुज-व्यास परियोजना का अंत हो रहा था तो वहां सब मिला कर के 36,322 मजदूर छटनीग्रस्त हुए। यह अक्टूबर 77 से मार्च 78 तक की बात है और मजदूरों की यूनियन से जो समझौता हुआ, उस समझौते में जो टर्म्स आफ सैटिलमेंट है, उस को आप देखें।

"The management promised that they would however continue their efforts to help the retrenched workmen to get jobs elsewhere both in private and government undertakings".

आप सैटलमेंट प्रामिज करते हैं लेकिन जो छंटनीग्रस्त होते हैं उन को सैटल जब नहीं किया जाता है तो यह बात समझ में नहीं आती है। यह ठीक है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने इन लोगों की तरफ कुछ ध्यान दिया है और राज्य सरकार की सर्विस में लेने के वास्ते आयु सीमा में कुछ छूट दी है, उस को बढ़ा दिया है और इस के लिए दोनों सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं लेकिन जो प्लैसमेंट सैल है और 1978 में जिस को बनाने की बात हुई थी उस में कितना काम हुआ है ? पहले में जो सैटिलमेंट हुआ था कि सब लोगों को दूसरी जगह काम देंगे और दूसरी यह भी हुआ था कि जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में लोग काम करते हैं drawing wages exceeding Rs. 500 p.m. in lieu of terminal benefits.

उन को भी देखेंगे और ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सग्रेशिया पेमेंट भी करेंगे और आधा देंगे क्या उस सब पर अमल हुआ है ? कुल पांच एग्रीमेंट हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के मजदूरों के साथ जो समझौते हुए थे एक से लेकर पांच तक इन में से किन किन का कार्यान्वयन हुआ है और कौन कौन बाकी है ?

36322 आदमी छंटनीग्रस्त हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन में से चाहे राज्य सरकार ने और चाहे आपने अब तक कितनों को काम पर लिया है ?

अक्सर ऐसा होता है कि जो मजदूर खून पसीना बहा कर काम करते हैं और योजना को पूरा करते हैं तो उस को पूरा हो जाने पर वे कहीं के नहीं रहते हैं और हमारी सरकार ही या सभापति महोदय आपकी हो दूसरी जगह कोई योजना बनती है तो नये लोगों को रख लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को सिद्धान्ततः इस बात को मान लेना चाहिए कि जिन लोगों ने तीन चार या पांच बरस काम किया है और उन की अगर छंटनी होनी है --योजना पूरी हो जाने पर और यह बात समझ में भी आती है तो उन को जो नई योजना शुरू होगी उस में प्राथमिकता दे कर रख लिया जाएगा। अगर

[डा० रामजी सिंह]

यह सिद्धान्त आप नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। हमारे यहां लाल मटिया कोयला खदान में दो हजार लोग काम करते थे। उस का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन वे अभी तक भी भूखे मर रहे हैं। दूसरी जगह कोई योजना शुरू होती हैं तो उसमें दूसरे लोगों को काम पर रख लिया जाता हैं। यह गलत हैं इस वास्ते मेरा पहला प्रश्न यह हैं कि पांच में से कितने समझौतों का पालन हुआ है और कहां तक हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? दूसरी बात यह है कि क्या सरकार जब नई परियोजना शुरू करती है तो उस में इन छंटनीग्रस्त लोगों को प्राथमिकता देगी या नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नई योजना में आज तक कितने इन लोगों को आपने लिया है और बाकी के छंटनीग्रस्त लोग बचे थे उन को क्यों नहीं लिया है?

SHRI P. RAMACHANDRAN: The hon. Member has raised some new points.

He desires to know as to how many clauses of the agreement have been implemented. After all, these points raised in the agreement are about the retrenchment benefits. According to the agreement, the retrenchment benefits have been given to all those employees who have been retrenched. And about their placement in other projects, as and when vacancies arise, as and when the projects are taken up, definitely, these people are given the very first preference. As a matter of fact, about 5,000 workers out of the retrenched workers have been found employment elsewhere. The placement cell is very much working there. All those who have been retrenched are absorbed there. These lists are being circulated to various project areas These project authorities are being persuaded to accept some of the employees or all the employees retrenched from there. In these cases, it is very difficult for us to force other project authorities to take all the employees retrenched here. It is only because of that difficulty that a number of benefits are given to those retrenched employees as a sort of compensation, and in a project like this, we cannot afford to keep all the employees till the end of the project. That is also the difficulty. It is a big project, and there are many phases of work. As and when these phases of work are completed, the employees have to be retrenched. Otherwise, it will be a great burden on the project itself. In a big project like this, there would be 50,000 people working at a particular period of time and we will not be able to keep all the employees till the project is completed or till alternate jobs are found for them, because it will be a great strain on the project itself. Then, this project is being executed on behalf of the States concerned. States like Rajasthan, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana etc. are concerned. These States are contributing money for the execution of these projects. Anything that we do will have to be done with the consent of these partner Sates. We are trying to see that these employees are not put to great difficulties about their livelihood. That is why, this compensation is given, retrenchment benefits are given and they are also helped to get jobs elsewhere.

DR. RAMJI SINGH: I want a clarification. In your reply to Question No. 5724 by Shri Sivaji Patnaik, you have enumerated different steps that the Government are taking to provide employment to these retrenched workers. You have enumerated eleven steps there. How many of these things have you been able to fulfil by now?

SHRI P. RAMACHANDRAN: All these steps are being fulfilled gradually. The only thing is this. Suppose we suggest to these people to go to some other project, some of them are not prepared to move out of the area, even if the employment is available. It is very difficult to see that all the people are employed in the nearby area. That is why, we circulate the names of the re-

trenched employees to other projects also. We also write to them and ask them to give some priority and preference to these employees and when they give preference some of the employees are not prepared to go to the far off places. That is our difficulty. It is our endeavour to see to help them in placing them in various projects.

DR. RAMJI SINGH: You are going to have many super-thermal power stations. Will you assure the House that these retrenched workers will be employed in those power projects?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Definitely, if they are found suitable for the particular type of work; and if they are willing to go to the project areas, their cases will be considered sympathetically and favourably.

श्री भगत राम : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मजदूर लोंग दूसरी जगहों पर काम करने नहीं जाते हैं। 39 हजार की रिट्चमेंट में से 9 हजार को काम मिला है। वह इसलिये नहीं जाते हैं कि लास्ट-पे उन की प्रोट्रेक्ट नही होती है, भुखमरी की मजदूरी दी जाती है। सब को काम नहीं मिलता है। मैं ने यूनियन के लीडरों की विक्टमाइजेशन का प्रश्न उठाया था उसका भी जवाब नहीं दियां। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो तीन महीने का वेतन मिला है यह स्टेट ने दिया है या सेंटर ने दिया है।

SHRI P. RAMACHANDRAN: Yes. It is out of the funds given by these partner-States that these benefits were paid.

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned, to reassemble at 11 a. m. on Monday, the 18th December.

17.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 18, 1978/Agrahayana 27, 1900 (Saka).